

प्रेषक,

सी० एस० नपलच्याल,
सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री नारायण दत्त तिवारी,
मा० पूर्व मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

दिनांक : 17, अक्टूबर, 2016।

विषय :- मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मा० भूतपूर्व मुख्यमंत्रीगणों को आवंटित शासकीय आवासों को रिक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में आप भिन्न हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री निवास स्थान आवंटन नियमावली-1997, जो उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त लागू है, के संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दि० 01, अगस्त, 16 को " उत्तर प्रदेश राज्य के मा० पूर्व मुख्यमंत्रीगणों को 02 माह के भीतर आवंटित शासकीय आवासों को रिक्त कर, उसका कब्जा राज्य सरकार को हस्तगत किये जाने तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मा० पूर्व मुख्यमंत्रीगणों से, उनको आवंटित आवास की तिथि से किराया वसूलने " संबंधी आदेश पारित किये गये हैं। "

2- उक्तानुसार पारित आदेश के क्रम में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन सं०-90(PIL)/2010 रुल लिटिगेशन एण्ड एनटाइटिलमेंट केन्द्र (RLEK) बनाम राज्य व अन्य के संबंध में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की ओर से लिये गये निर्णय के संबंध में अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

3- तदक्रम में आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री निवास स्थान आवंटन नियमावली-1997, जो उत्तराखण्ड राज्य में यथावत लागू है, जिसके अनुरूप ही आपको शासकीय आवास आवंटित किये गये हैं, भी उक्तानुसार मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अछादित है। अतः उक्त के परिपेक्ष्य राज्य सरकार द्वारा आपको आवंटित शासकीय आवास सं०-अनन्त वन, एफ.आर.आई, कैम्पस, लेन नं०-01, वृक्षगढ रोड, देहरादून की निरंतरता बनाया रखना संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त वस्तु-स्थित के आलोक में आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको आवंटित शासकीय आवास सं०-अनन्त वन, एफ.आर.आई, कैम्पस, लेन नं०-01, वृक्षगढ रोड, देहरादून को 16, दिसम्बर, 2016 तक रिक्त करते हुए, उसका कब्जा मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को हस्तगत करने का कष्ट करे। उक्त के अतिरिक्त आवंटित आवास के अध्यारोपित किराये को आगणित करते हुए, किराये की वसूली हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।

भवदीय,

(सी० एस० नपलच्याल)
सचिव।

संख्या: 1331/xxxii-2-2016-3(31)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन /मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, विधानसभा सचिवालय, /सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड/निजी सचिव, मा० मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, विधानसभा, उत्तराखण्ड/निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन/राज्य सम्पत्ति अनु-01 एवं 03/गोपन(मंत्रिपरिषद्) विभाग/सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्तानुसार आवंटित आवास को रिक्त किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें/एन०आई०सी०, देहरादून/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।